बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 236 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 07 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

100 में ऑनलाइन बनता था फर्जी आधार और वोटर आईडी, दिल्ली पुलिस ने किया रैकेट का पर्दाफाश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में संगठित साइबर जालसाजी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट ने एक ऐसे अंतर-राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो एक वेबसाइट के जरिए बड़े पैमाने पर फर्जी सरकारी पहचान पत्र बनाने और उन्हें ऑनलाइन बेचने के काले धंधे में शामिल था। पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान विदेशी साव और संतोष कुमार के रूप में हुई है। यह गिरोह बीके प्रिंट डाट इन नाम की वेबसाइट के जरिए नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज तैयार कर रहा था .

दिल्ली नगर निगम के वार्ड कमेटियों के चुनाव की अधिसूचना जारी, 10 जुलाई तक नामांकन और 15 को होगा मतदान

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 जुलाई तक नामांकन होंगे जबकि, 15 जुलाई को मतदान होगा। यह चुनाव सिर्फ जोन की सत्ता तय नहीं करेंगे, बल्कि एमसीडी की सबसे ताकतवर स्थायी समिति के गठन का रास्ता भी साफ करेंगे। यही वजह है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने-अपने स्तर पर राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी दिल्ली के 12 जोनों में से 8 पर भाजपा और 4 पर आम आदमी पार्टी का नियंत्रण है। भाजपा इस बार अपने सभी जोन बरकरार रखने के साथ रोहिणी और पश्चिमी जोन में भी जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। वार्ड कमेटियों के चुनाव एमसीडी प्रशासन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर जोन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इन्हीं वार्ड कमेटियों के जरिए स्थायी समिति के सदस्य चुने जाएंगे।

स्थायी समिति करोड़ों रुपये के विकास कार्यों, बड़े ठेकों, वित्तीय प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर अंतिम निर्णय लेने वाली एमसीडी की सबसे शक्तिशाली समिति है। इसी वजह से इन चुनावों को एमसीडी की सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है।

नेतन्याहू के भारत समर्थन वाले बयान पर सरकार पर बरसी कांग्रेस, कहा- विश्वगुरु की चुप्पी अस्वीकार्य

नई दिल्ली । इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याह की तरफ से भारत के समर्थन का दावा किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि इस्राइल की सैन्य कार्रवाइयों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी भारत की सभ्यतागत परंपराओं और मूल्यों के खिलाफ है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि नेतन्याहू का यह कहना गलत है कि भारत इस्राइल के साथ खड़ा है।

उन्होंने कहा कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल के प्रति झुकाव रखते हों, लेकिन करोड़ों भारतीय गाजा में हो रही हिंसा, फलस्तीनियों के विस्थापन, ईरान पर हमलों और दक्षिणी लेबनान में इस्राइली सैन्य अभियान की निंदा करते है। उनके अनुसार, ये सभी घटनाएं मानवता पर हमला हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू से समर्थन या प्रशंसा मिलना कोई सम्मान की बात नहीं है। रमेश ने दावा किया कि खुद नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ चुके हैं और उनके प्रति अमेरिका में भी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल, अमेरिकी समाचार चैनल को दिए एक साक्षात्कार में नेतन्याहू ने कहा कि इस्राइल को केवल अमेरिका का ही नहीं, बल्कि भारत जैसे अन्य देशों का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भारत एक छोटा देश नहीं, बल्कि 1.4 अरब आबादी वाला देश है और वहां से उन्हें जबरदस्त समर्थन मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर उन्हें भारत से बड़ी संख्या में समर्थन संदेश मिलते है। नेतन्याहू का यह बयान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की हालिया टिप्पणी के जवाब में आया। पिछले महीने वेंस ने कहा था कि यदि इस्राइल अमेरिकी नीतियों की आलोचना करता है, तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका उसका सबसे शक्तिशाली सहयोगी है। इसी टिप्पणी का जवाब देते हुए नेतन्याहू ने भारत सहित अन्य देशों के समर्थन का जिक्र किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी के रुख पर सवाल उठाए है। हालांकि, सरकार की ओर से कांग्रेस के आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सभी 5633 स्कूलों में बनेगी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, महीनेभर में पूरी करनी होगी व्यवस्था; एलजी के निर्देश

नई दिल्ली । दिल्ली के सभी 5633 सरकारी, सहायता प्राप्त, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट और निजी स्कूलों में इस महीने के अंत तक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का गठन अनिवार्य होगा। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बाल सुरक्षा माह (चाइल्ड प्रोटेक्शन मंथ) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी सुरक्षा उपाय लागू करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अभियान केवल जुलाई तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सभी संस्थानों में इन्हें स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया जाएगा। उच्चस्तरीय बैठक में बताया गया कि फिलहाल दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में पॉक्सो कानून के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां गठित हो चुकी हैं। इस पर एलजी और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राजधानी के सभी 5633 स्कूलों में इसी महीने के भीतर ऐसी समितियों का गठन सुनिश्चित किया जाए। ये समितियां बच्चों की सुरक्षा, शिकायतों की निगरानी और कानून के पालन की जिम्मेदारी

निभाएंगी। बैठक में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज हर मामले में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ मामलों की जांच और कार्रवाई की निगरानी होगी। प्रत्येक जिले में अतिरिक्त डीसीपी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे। बैठक में सभी स्कूलों में स्टूडेंट सेफ्टी चेकलिस्ट लागू करने, पॉक्सो मामलों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने और शिक्षकों व मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अभिभावकों, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली पुलिस और स्कूल प्रमुखों की संयुक्त निरीक्षण टीमें गठित कर सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। सरकार ने सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, साइबर सुरक्षा, बुलिंग, नशे से बचाव और व्यक्तिगत सीमाओं जैसे विषयों पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। अभी करीब 1000 एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर (ईवीजीसी) सरकारी स्कूलों में जागरूकता सत्र ले रहे हैं। बैठक में निर्देश दिया गया कि ऐसी व्यवस्था भविष्य में राजधानी के हर स्कूल तक पहुंचाई जाए। साथ ही पीटीएम, ऑडियो-वीडियो सामग्री, मोबाइल जागरूकता वैन और प्रिंट प्रचार के माध्यम से अभिभावकों और बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा। बैठक में पहली बार अपराध करने वाले किशोरों के प्रति सुधारात्मक नीति अपनाने पर भी सहमति बनी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे किशोरों के लिए काउंसलिंग और पुनर्वास की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिल सके। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागवार प्रस्तुतियां दीं। समीक्षा के बाद एलजी और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग तय समयसीमा में कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करें। उनका कहना था कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और इसके लिए संस्थागत व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत किया जाएगा।

किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है बच्चे का अपने असली माता-पिता को जानना, दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली।बच्चे का अपने जैविक माता-पिता की पहचान जानने का अधिकार किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सामाजिक कलंक की आशंका से अधिक महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए परिवार अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक व्यक्ति और तीन बच्चों का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि उसका उद्देश्य सत्य तक पहुंचना और बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना है, इसलिए प्रतिष्ठा को सत्य की पड़ताल के रास्ते में ढाल नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि बच्चे वयस्कों के निर्णयों का खामियाजा नहीं भुगत सकते। जैविक माता-पिता की पहचान केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि बच्चे की पहचान, गरिमा, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और अन्य वैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए ऐसे मामलों में अदालत का दायित्व सत्य का पता लगाना है। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य केवल पक्षकारों के बीच विवाद का निपटारा करना नहीं, बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना भी है। इसलिए ऐसे मामलों में बच्चे का सच जानने का अधिकार सर्वोपरि रहेगा। मामला उस व्यक्ति की याचिका से संबंधित था, जिसने परिवार अदालत के मार्च 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। परिवार अदालत ने भरण-पोषण विवाद की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और तीन बच्चों का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। व्यक्ति का दावा था कि वह महिला का पति नहीं है और बच्चों का जैविक पिता भी नहीं है। उसका कहना था कि डीएनए जांच से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उसकी विधिक पत्नी एक सार्वजनिक पद पर कार्यरत है। महिला की ओर से अदालत में दलील दी गई कि बच्चों के पितृत्व का निर्धारण भरण-पोषण के मामले के निष्पक्ष निस्तारण के लिए आवश्यक है और इसके लिए डीएनए परीक्षण सबसे विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सामाजिक बदनामी की आशंका के आधार पर सत्य की जांच नहीं रोकी जा सकती। यदि डीएनए परीक्षण से विवाद का वास्तविक तथ्य सामने आ सकता है और बच्चे के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है, तो अदालत ऐसे परीक्षण का आदेश देने से पीछे नहीं हट सकती।

केजरीवाल ने पूछा कौन हैं नितिन नबीन? प्रवेश वर्मा का चुटीला जवाब- क्या मैं याद हूँ?

नई दिल्ली ।आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद अब एक राजनीतिक घमासान में बदल गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर सीएम रेखा गुप्ता ने तीखा हमला किया है, जबकि डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने अनोखे अंदाज में पलटवार किया है। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के विवाद के बीच, हिंदू देवी-देवताओं के अपमान पर विपक्षी नेताओं के चुप रहने का आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता नितिन नवीन पर केजरीवाल ने निशाना साधा। नवीन ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल का नाम लेते हुए कहा था कि वे हिंदू धर्म को इतना कमजोर न समझें कि लोग आपकी बातों में आ जाएंगे। एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए आप प्रमुख ने नितिन नवीन से पूछा, आप कौन हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल की आलोचना करते हुए उनके बयान को हताशा की निशानी बताया। इसके बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने अहंकार में चूर हैं, जबकि हर कोई जानता है कि वह हताश और निराश हैं। बीजेपी नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने नितिन नबिन के मामले में अरविंद केजरीवाल के आप कौन हैं? वाले सवाल का छोटा लेकिन दिलचस्प जवाब दिया। वर्मा ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको मैं याद भी हूं या नहीं?

35 किमी लंबे रूट पर 28 मेट्रो स्टेशन, गुरुग्राम को मिलेगी रफ्तार; सेक्टर-56 से पचगांव तक बेहतर होगी कनेक्टिविटी

नई दिल्ली। गुरुग्राम को विश्वस्तरीय सुविधा संपन्न शहर बनाने के लिए नायब सरकार शहर में मेट्रो विस्तार पर जोर दे रही है। इसके लिए सेक्टर-56 से दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित पचगांव तक ग्लोबल सिटी को जोड़ते हुए प्रस्तावित मेट्रो रूट की डीपीआर को प्रदेश सरकार जल्द सैद्धांतिक मंजूरी दे सकती है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की तरफ से तैयार की गई डीपीआर में 35 किलोमीटर लंबे रूट पर 28 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इस योजना पर करीब 10 हजार 428 करोड़ की रकम खर्च होगी। इसका 20प्रतिशत हिस्सा हरियाणा सरकार और 10फीसदी हिस्सा केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय वहन करेगा, बाकी 70 प्रतिशत राशि बैंकों से लोन लेकर जुटाई जाएगी। विमर्श कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेट्रो डीपीआर का अध्ययन किया जा रहा है। अगले सप्ताह तक इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद रूट तैयार करने की प्रकिया आरंभ कर दी जाएगी। इस नए रूट को सेक्टर-37 में करीब एक हजार एकड़ में बन रही ग्लोबल सिटी से कनेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की ओर से परियोजना के लिए 1500 करोड़ की रकम दी जाएगी। ग्लोबल सिटी मे आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाई होंगी।

सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम..., छात्रों से ऐसा क्यों बोले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके

नई दिल्ली । नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार जारी है. इस आंदोलन को समर्थन दे रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले नौ दिनों से अनशन पर हैं. उनके साथ कुछ छात्र भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हालांकि उन्हें लगातार अनशन खत्म करने के लिए समझाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर सीजेपी बनाकर चर्चा में आए अभिजीत दीपके ने भी छात्रों से अपील की है कि वे अनशन न करें. उनका कहना है कि यह आंदोलन लंबा चल सकता है और ऐसे में सभी लोगों का स्वस्थ और सक्रिय रहना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को अनशन का अनुभव है, इसलिए उन्हें यह जारी रखने देना चाहिए, जबकि बाकी लोगों को आंदोलन की दूसरी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए. जानकारी के अनुसार, सोनम वांगचुक लगातार 9 दिनों से अनशन पर हैं और इस दौरान उनका वजन भी तेजी से कम हुआ है. सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय

हुए अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर उम्मीद के मुताबिक बड़ी भीड़ जुटाने में सफल नहीं हो पाए हैं. इसके बावजूद वे अपने समर्थकों और छात्रों के साथ लगातार प्रदर्शन में शामिल हैं. एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे भूख हड़ताल पर न बैठें. उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग अनशन करेंगे तो आंदोलन को आगे कौन संभालेगा. उनके मुताबिक, अगर सरकार को इस मुद्दे की चिंता होती तो बच्चों की मौत या पेपर लीक की घटना के बाद ही कार्रवाई हो जाती. इसलिए उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि यह लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है. दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक को लंबे समय तक अनशन करने का अनुभव है और वे खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन छात्रों की सेहत को लेकर उन्हें चिंता है.

उन्होंने दोबारा अपील करते हुए कहा कि आंदोलन को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है. अगर सभी लोग अनशन पर बैठ जाएंगे तो प्रदर्शन की बाकी व्यवस्थाएं कौन संभालेगा. इस बीच, कुछ दिन पहले सोनम वांगचुक ने भी प्रदर्शन स्थल पर जुटने वाले लोगों से एक दिन का प्रतीकात्मक उपवास रखने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि कई लोग वहां भरपेट भोजन कर रहे हैं, जबकि अनशन करने वाले लोग भूखे है.

सम्पादकीय...

बढ़ती भूमिका

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में भारत को इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक बताते हुए दोनों देशों के मजबूत संबंधों की खुलकर सराहना की। अमेरिकी समाचार चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि भारत जैसे महत्वपूर्ण मित्र भी है, जहां उसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने टिप्पणी की थी कि अमेरिका के अलावा इजराइल का कोई शक्तिशाली सहयोगी नहीं है। नेतन्याहू की प्रतिक्रिया को केवल एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि भारत-इजराइल संबंधों की बदलती प्रकृति और वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। साक्षात्कार के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि भारत एक छोटा नहीं, बल्कि 1.4 अरब आबादी वाला विशाल देश है और वहां इजराइल के प्रति जबरदस्त समर्थन देखने को मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के कई देशों के नेता उनसे संपर्क करते हैं, रक्षा समझौते करना चाहते हैं और इजराइल की सैन्य क्षमताओं से सीखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार, यह धारणा सही नहीं है कि इजराइल केवल अमेरिका पर निर्भर है। हालांकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में इजराइल का सबसे बड़ा मित्र भी बताया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के प्रति सम्मान व्यक्त किया। भारत और इजराइल के संबंध पिछले तीन दशकों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुए हैं। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद रक्षा, कृषि, विज्ञान, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में इजराइल भारत के प्रमुख साझेदारों में शामिल है। आधुनिक ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणाली, निगरानी उपकरण और अन्य अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा और उसके बाद इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा ने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दी। इन यात्राओं के दौरान कृषि नवाचार, जल संरक्षण, रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग से जुड़े अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध केवल रक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि नवाचार, स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ। हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया में गाजा, लेबनान और ईरान से जुड़े संघर्षों के दौरान भारत ने संतुलित विदेश नीति अपनाने का प्रयास किया है। भारत ने एक ओर आतंकवाद की निंदा करते हुए इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार किया है, वहीं दूसरी ओर गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने और दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन भी दोहराया है। यही संतुलित नीति भारत को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और विश्वसनीय शक्ति के रूप में स्थापित करती है। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है जब इजराइल को गाजा युद्ध, ईरान के साथ तनाव और लेबनान में सैन्य अभियानों को लेकर अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अनेक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय संकट और युद्धविराम की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की है। ऐसे माहौल में भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का उल्लेख करना इजराइल के लिए कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साक्षात्कार में नेतन्याहू ने लेबनान को लेकर भी अपनी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण लेबनान के कुछ ईसाई गांवों ने हिज्बुल्लाह के खतरे से सुरक्षा के लिए स्वयं इजराइल में शामिल होने की इच्छा जताई है। उनके अनुसार, इजराइल उन समुदायों की रक्षा कर रहा है जिन्हें हिज्बुल्लाह से खतरा है। हालांकि इस दावे पर लेबनान की ओर से अलग दृष्टिकोण सामने आ सकता है और यह विषय क्षेत्रीय राजनीति में विवाद का कारण बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल के संबंध लंबे समय से अत्यंत घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन हाल के महीनों में अमेरिका द्वारा ईरान के साथ युद्धविराम और समझौते की दिशा में उठाए गए कदमों ने नई बहस को जन्म दिया है। जेडी वेंस की टिप्पणी भी इसी संदर्भ में सामने आई थी। उनका संकेत था कि इजराइल को अपने प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ सार्वजनिक मतभेदों से बचना चाहिए। नेतन्याहू ने इसका उत्तर देते हुए यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि इजराइल के वैश्विक स्तर पर अनेक मित्र देश हैं और भारत उनमें प्रमुख स्थान रखता है। भारत के लिए भी इजराइल एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, जल संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप सहयोग और रक्षा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। साथ ही भारत पश्चिम एशिया के अन्य देशों, विशेषकर खाड़ी देशों और ईरान, के साथ भी मजबूत संबंध बनाए हुए है। यही संतुलित कूटनीति भारत की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत और इजराइल के संबंध और गहरे हो सकते हैं। रक्षा विनिर्माण, उन्नत तकनीक, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का समर्थन करता रहेगा। अंततः, बेंजामिन नेतन्याहू का भारत को लेकर दिया गया बयान केवल एक प्रशंसा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव की स्वीकारोक्ति है। आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, सबसे बड़े लोकतंत्र और उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है। ऐसे में भारत-इजराइल संबंध केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बदलते वैश्विक सामरिक और कूटनीतिक समीकरणों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। आने वाले समय में यह साझेदारी दोनों देशों के साझा हितों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

ऊर्जा संकट और मोदी सरकार

पश्चिम एशिया में युद्ध संकट के दौरान भारत ने जिस तरह ऊर्जा सप्लाई के संकट का सामना किया और देश में ईंधन, पैट्रोल व डीजल सहित गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित किया वह वास्तव में नीतिगत स्तर से लेकर व्यावहारिक स्तर तक नागरिकों की समस्याओं को समाधान करने वाला था। अतः इस कथन में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि 21वीं सदी के अभी तक के इस सबसे बड़े ऊर्जा संकट के समय सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने बहुत संयम और धैर्य से काम लेते हुए अपने कूटनीतिक सम्बन्धों के जरिये पैट्रोल व डीजल सहित ईंधन गैस की सप्लाई के वैकल्पिक मार्ग खोजते हुए भारत के लोगों को वे कष्ट नहीं होने दिये जो विश्व के अन्य देशों के लोग झेल रहे थे। ईरान-इजराइल व अमेरिका युद्ध के दौरान सरकार ने एक तरफ देश के हर पैट्रोल पंप पर पैट्रोल व डीजल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की और दूसरी तरफ इनके खुदरा दामों को भी नहीं बढ़ने दिया। हालांकि ईंधन गैस सप्लाई के मोर्चे पर कुछ दिक्कतें आयीं और इसकी सप्लाई में भी देश के सुदूर क्षेत्रों में अवरोध पैदा हुए और कुछ दाम भी बढ़ाने पड़े परन्तु कमोबेश तरीके से इस पर भी नियन्त्रण रखने की पूरी कोशिश की गई। इसलिए प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह कहना पूरी तरह तार्किक है कि 'संकट के समय भारत की कूटनीति का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध ही संकट की घड़ी में बहुत काम आये'। श्री मोदी ने ये शब्द तब कहे जब वह बीते दिन राजस्थान के बलोत्तरा संभाग के पचपदरा में देश के पहले ग्रीन फील्ड एकीकृत तेल शोधन व पैट्रोकेमिकल परियोजना परिसर को देश को समर्पित कर रहे थे। इस परियोजना के चालू होने से भारत विश्व का चौथा ऐसा सबसे बड़ा देश हो जायेगा जिसकी तेल परिशोधन की क्षमता सर्वाधिक है जबकि दूसरी तरफ भारत अभी भी अपनी ऊर्जा सप्लाई की जरूरत 80 प्रतिशत आयात करके ही करता है। इसका मतलब यह निकलता है कि भारत कच्चे तेल के परिशोधन के मामले में दुनिया का एक बड़ा केन्द्र होने में तेजी से अग्रसरित हो रहा है। जहां तक भारत की कूटनीति का प्रश्न है तो पश्चिम एशिया युद्ध के समय देश के विपक्षी दलों व इनके नेताओं ने मोदी सरकार की विदेश नीति की कटु से कटुतम आलोचना यहां तक की कि इसे अमेरिका का पिछलग्गू तक बता दिया परन्तु मोदी सरकार ने इस

> ईरान- इजराइल व अमेरिका युद्ध के दौरान सरकार ने एक तरफ देश के हर पैट्रोल पंप पर पैट्रोल व डीजल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की और दूसरी तरफ इनके खुदरा दामों को भी नहीं बढ़ने दिया। हालांकि ईंधन गैस सप्लाई के मोर्चे पर कुछ दिक्कतें आयीं और इसकी सप्लाई में भी देश के सुदूर क्षेत्रों में अवरोध पैदा हुए और कुछ दाम भी बढ़ाने पड़े परन्तु कमोबेश तरीके से इस पर भी नियन्त्रण रखने की पूरी कोशिश की गई। इसलिए प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह कहना पूरी तरह तार्किक है कि 'संकट के समय भारत की कूटनीति का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध ही संकट की घड़ी में बहुत काम आये'।

सबकी परवाह न करते हुए ऊर्जा सप्लाई के अन्य वैश्विक स्रोतों को खोजा और फारस की खाड़ी के समुद्री मार्ग के बन्द होने के बावजूद उससे कच्चे तेल की सप्लाई के अन्य समुद्री मार्ग खोले। युद्ध से पहले जहां भारत लगभग 25 देशों से तेल का आयात करता था वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 45 के लगभग हो गई है। इसके समानान्तर युद्ध की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के अनाप-सनाप दाम बढ़ने की वजह से घरेलू बाजार में पैट्रोल व डीजल के भाव बढ़ने का खतरा अलग से था जिसे केन्द्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में दस रुपये प्रति लीटर की कमी करके सन्तुलित करने का प्रयास इस तरह किया कि पैट्रोल पंपों पर इनके दाम स्थिर बने रहे। घरेलू बाजार में दाम स्थिर रखने की कवायद में भारत की तेल कम्पनियों को हालांकि 75 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ परन्तु सरकार ने इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया और छिटपुट रूप से ही पैट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाये तथा इनकी निर्बाध सप्लाई जारी रखी। श्री मोदी इस बाबत यह कहने से नहीं चूके कि जब भारत के लोग पश्चिम एशिया के संकट से जूझ रहे थे तो कुछ राजनैतिक दल व नेता लोगों में घबराहट पैदा करने व उन्हें भड़काने के काम में लगे हुए थे और उनमें असुरक्षा की भावना को बल दे रहे थे परन्तु उनकी सरकार की नीतियों व जमीनी व्यावहारिक कदमों की वजह से ऐसा नहीं हो सका और विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। इसका प्रमुख कारण यह है कि श्री मोदी की सरकार की नीतियां सामान्यतः जन कल्याण को केन्द्र में रख कर बनाई जा रही हैं। अर्थव्यवस्था के इस बाजारीकरण के दौर में 'कल्याणकारी राज' की संवैधानिक परिकल्पना को मूर्त रूप देना आसान काम नहीं है क्योंकि इस व्यवस्था में हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र व विदेशी निवेश को महत्ता देना सरकार की मजबूरी होता है अतः इस वातावरण में समाज के सबसे गरीब व पिछड़े व्यक्ति के हितों का संरक्षण करने के साथ विकास का सोपान चढ़ना बहुत ही पेचीदा होता है। यही वजह है कि मोदी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन की सुविधा दे रही है जिसे प्रायः आलोचक भारत की गरीबी से जोड़ कर देखते हैं मगर वे भूल जाते हैं कि किसी भी लोकतन्त्र में सरकार का पहला धर्म आर्थिक रूप से विपन्न जनता की भूख से लेकर उसकी आवास व स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने का ही होता है। इस मोर्चे पर मोदी सरकार अपने सत्तारूढ़ होने के पहले वर्ष से ही बहुत सतर्क है और उसने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं जिनमें पांच लाख रुपये तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा भी शामिल है। लोकतन्त्र में सरकार के इकबाल की सबसे बड़ी पहचान भी यही होती है कि गरीब जनता के मन में उस सरकार की छवि कैसी है। अतः पश्चिम एशिया संकट के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की समीक्षा हम इसी पैमाने से करेंगे। बेशक इस संकट की वजह से भारत में महंगाई बढ़ी है और आवश्यक खाद्य वस्तुओं व सेवाओं के दाम तेज हुए हैं मगर इन पर काबू तभी पाया जा सकता है जब समन्वित रूप से सरकारी व निजी क्षेत्र मिल कर काम करें और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। अतः श्री मोदी जब यह कहते हैं कि उनकी सरकार के लिए 'नागरिक देवो भव' एक मन्त्र के रूप में काम करता है तो उनके पिछले 12 वर्ष की शासन पद्धति की समालोचना आसानी से हो जाती है। इस मामले में देश की जनता की सूझबूझ की भी सराहना करनी पड़ेगी कि वह भी संकट के समय विचलित करने वाले भ्रामक प्रचार के चक्कर में नहीं पड़ी और उसने संयम बनाये रखा।

ट्रंप और मेलोनी के बीच बढ़ता टकराव- क्या पश्चिमी सहयोगियों के रिश्तों में आ रही है दरार?

विश्व राजनीति में नेताओं के व्यक्तिगत बयान कई बार देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को भी प्रभावित कर देते हैं। विशेष रूप से तब, जब वह बयान सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया पर दिए जाएं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच बढ़ा विवाद इसी बात का उदाहरण है। दोनों नेताओं के बीच पहले से चल रही तल्खी उस समय फिर चर्चा में आ गई, जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर जी-7 शिखर सम्मेलन की एक तस्वीर साझा करते हुए उसके ऊपर लिखा– रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर नीडेड (प्रतिबंधात्मक आदेश की आवश्यकता है)। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका इशारा किस ओर था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे मेलोनी पर कटाक्ष के रूप में देखा गया। दरअसल, यह विवाद जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू हुआ था, जिसमें भारत सहित दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता शामिल हुए थे। सम्मेलन के बाद ट्रंप ने दावा किया कि जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बेहद उत्सुक थीं और उन्होंने बार-बार इसकी इच्छा जताई। ट्रंप ने यहां तक कहा कि उन्होंने केवल तरस खाकर उनके साथ तस्वीर खिंचवाई। उनके अनुसार, मेलोनी उनसे बात करके भी बहुत खुश थीं और यह उनके लिए एक तरह का एहसान था। ट्रंप के इस बयान ने इटली में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इन सभी दावों को पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने कभी ट्रंप से तस्वीर की मांग की और न ही किसी प्रकार की विनती की। मेलोनी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इटली और मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगते। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगी देशों के नेताओं के बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिमी देशों के विरोधियों के प्रति उनका रवैया अपेक्षाकृत नरम रहता है। मेलोनी ने आगे कहा कि ट्रंप के बयान पूरी तरह काल्पनिक हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने मित्र देशों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। उनके इस बयान को इटली में राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देखा गया और अधिकांश राजनीतिक दलों ने भी प्रधानमंत्री का समर्थन किया। इस विवाद का असर केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो तायानी ने अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे सामान्य प्रशासनिक निर्णय बताया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का संकेत माना। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पहले तक जॉर्जिया मेलोनी को यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप की सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगियों में गिना जाता था। दोनों राष्ट्रवाद, अवैध प्रवासन पर सख्त नीति, पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों और दक्षिणपंथी राजनीति जैसे कई मुद्दों पर समान विचार रखते थे। यही कारण था कि उनके बीच अच्छे संबंधों की चर्चा होती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। इससे पहले ट्रंप ने ईरान संघर्ष को लेकर पोप लियो की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए जो बयान दिया था, उसकी भी मेलोनी ने आलोचना की थी। इसके बाद ट्रंप ने मेलोनी पर साहस की कमी का आरोप लगाया। अब जी-7 सम्मेलन के बाद तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद दोनों नेताओं के बीच बढ़ती दूरी को और स्पष्ट करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की राजनीतिक शैली पारंपरिक कूटनीति से अलग रही है।

जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए)- भारत-जापान संबंधों की मजबूत आधारशिला

भारत और जापान के संबंध केवल कूटनीतिक या व्यापारिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच विकास, विश्वास और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित एक दीर्घकालिक सहयोग का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की तीन दिवसीय भारत यात्रा ने इस साझेदारी को नई गति प्रदान की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, धातु, रक्षा तथा आपूर्ति श्रृंखला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भारत के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और जापान अपनी-अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक-दूसरे को सशक्त बनाएंगे और साझा समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस यात्रा के दौरान सबसे अधिक चर्चा जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) को लेकर हुई। मार्च 2026 में जापान ने भारत को लगभग 16,420 करोड़ रुपये की रियायती विकास सहायता प्रदान करने की घोषणा की। यह राशि पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र में शहरी परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि विकास से जुड़ी चार प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। इस निर्णय ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि भारत और जापान के संबंध केवल रक्षा या व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच विकास आधारित साझेदारी भी अत्यंत मजबूत है। जापान का आधिकारिक विकास सहायता कार्यक्रम वर्ष 1954 में कोलंबो योजना से जुड़ने के बाद विकसित हुआ। इस योजना का उद्देश्य एशियाई देशों के आर्थिक और तकनीकी विकास में सहयोग करना था। भारत इस कार्यक्रम का पहला लाभार्थी देश बना, जिसे वर्ष 1958 में पहली बार जापान से ओडीए ऋण प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय विकास सहयोगी बना हुआ है। ओडीए का अर्थ है किसी विकसित देश द्वारा विकासशील देशों को कम ब्याज दर, लंबी पुनर्भुगतान अवधि और रियायती शर्तों पर सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होता है। जापान यह सहायता मुख्य रूप से तीन माध्यमों से प्रदान करता है– रियायती ऋण, अनुदान तथा तकनीकी सहयोग। इन कार्यक्रमों का संचालन मुख्य रूप से जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाइका) द्वारा किया जाता है, जो भारत में भी इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रमुख संस्था है।

ओडीए और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के बीच मूलभूत अंतर भी समझना आवश्यक है। ओडीए सरकार से सरकार के बीच विकास परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता होती है, जबकि एफडीआई निजी कंपनियों द्वारा व्यापार विस्तार और लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला निवेश है। वर्ष 2000 से 2025 के बीच जापान ने भारत में लगभग 44 से 45 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, जो भारत में कुल विदेशी निवेश का लगभग छह प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अब केवल सहायता प्राप्त करने वाला देश नहीं, बल्कि जापान का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भी बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओडीए और एफडीआई एक-दूसरे के पूरक हैं। पहले ओडीए के माध्यम से सड़कें, रेल, मेट्रो, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है। जब विकास का आधार मजबूत हो जाता है, तब निजी कंपनियां निवेश के लिए आगे आती हैं। इस प्रकार ओडीए भविष्य के विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। भारत में जापानी ओडीए की सबसे बड़ी सफलता दिल्ली मेट्रो परियोजना मानी जाती है। वर्ष 1997 से अब तक जापान इस परियोजना के लिए लगभग 5.7 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान कर चुका है। इसी प्रकार मुंबई-अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना, जिसे आमतौर पर बुलेट ट्रेन परियोजना कहा जाता है, जापानी सहयोग का एक और बड़ा उदाहरण है। वर्ष 2023 में इस परियोजना के लिए अतिरिक्त 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने भारत में सात प्रमुख परियोजनाओं के लिए लगभग 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई। इनमें बेंगलुरु मेट्रो का तीसरा चरण, मुंबई मेट्रो लाइन-11, महाराष्ट्र में चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों का निर्माण तथा पंजाब में टिकाऊ बागवानी को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। यह राशि जापान द्वारा विश्वभर में वितरित कुल ओडीए का लगभग 10.4 प्रतिशत थी, जिससे भारत जापान का सबसे बड़ा विकास सहायता प्राप्तकर्ता बना। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी जापानी सहायता का महत्व लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 के बाद से जापान ने इस क्षेत्र में लगभग 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। यह निवेश भारत की एक्ट ईस्ट नीति और जापान की मुक्त एवं खुला हिंद-प्रशांत (फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक) रणनीति के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक माना जाता है। बेहतर सड़क, पुल, बिजली और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर-पूर्व भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने का प्रयास दोनों देशों की साझा रणनीति का हिस्सा है। भारत और जापान के संबंधों में वर्ष 1998 के पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षण के बाद कुछ समय के लिए ठहराव आया था। जापान ने अपनी परमाणु अप्रसार नीति के कारण नई विकास सहायता परियोजनाओं पर अस्थायी रोक लगा दी थी।

हालांकि वर्ष 2000 के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य हुए और 2006 में रणनीतिक वैश्विक साझेदारी स्थापित होने के बाद जापानी सहायता में तेजी से वृद्धि हुई। इसके बाद रक्षा, समुद्री सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग के नए आयाम विकसित हुए। जापान की विकास सहायता नीति को अक्सर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि दोनों की कार्यप्रणाली अलग-अलग है। जापान गुणवत्ता, पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक टिकाऊ विकास पर जोर देता है, जबकि चीन बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे के निर्माण और तेज निवेश मॉडल को प्राथमिकता देता है। भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल न होकर जापान के साथ विकास आधारित सहयोग को अधिक महत्व दिया है। हाल के वर्षों में जापान ने आधिकारिक सुरक्षा सहायता नामक नई पहल भी शुरू की है, जिसके माध्यम से मित्र देशों की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा है। यद्यपि भारत अभी इस योजना का औपचारिक लाभार्थी नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय लगातार मजबूत हो रहा है।

भारत के लिए जापानी ओडीए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। इससे देश को विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा, आधुनिक तकनीक, बेहतर परिवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और सतत विकास के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त होते हैं। वहीं जापान के लिए भारत एक विशाल बाजार, विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। अंततः, जापान की आधिकारिक विकास सहायता भारत-जापान संबंधों की सबसे मजबूत आधारशिलाओं में से एक है। लगभग सात दशक से जारी यह सहयोग आज केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक साझेदारी का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की भारत यात्रा और नई विकास सहायता परियोजनाएं इस बात का संकेत हैं कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा यह साझेदारी भारत के विकास के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समावेशी विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगी।

क्या यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार हो सकता है?

वैश्विक स्तरपर मध्य-पूर्व का इतिहास केवल युद्धों,तेल,परमाणु कार्यक्रमों और कूटनीतिक संघर्षों से नहीं लिखा गया है, बल्कि ऐसे प्रतीकात्मक आयोजनों से भी लिखा गया है जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों की राजनीति और जनमानस को प्रभावित किया।28 फरवरी 2026 को ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार ऐसा ही एक आयोजन बनता दिखाई दे रहा है। फरवरी में हुए अमेरिकी-इजरायली हमले में उनकी मृत्यु के बाद सुरक्षा कारणों से अंतिम संस्कार तत्काल नहीं किया जा सका और उसे कई महीनों के लिए स्थगित करना पड़ा। अब जुलाई में शुरू हुई बहु-दिवसीय अंतिम यात्रा को ईरानी नेतृत्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, शहादत, प्रतिरोध और राजनीतिक संदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अनेक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के अनुसार अंतिम यात्रा तेहरान से शुरू होकर विभिन्न धार्मिक स्थलों से गुजरते हुए 9 जुलाई को मशहद में दफन के साथ पूरी होगी।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया में लगातार देख रहा हूं कि ईरानी सरकारी मीडिया और कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में इसे फ्यूनरल ऑफ़ द सेंचुरी यानी शताब्दी का अंतिम संस्कार कहा जा रहा है। आयोजकों का दावा है कि पूरे कार्यक्रम में करोड़ों लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ अभी केवल लाखों से करोड़ों तक की संभावित भीड़ का उल्लेख कर रही है और अंतिम संख्या की पुष्टि बाद में होने की बात कह रही है। कुछ रिपोर्टों में 1.5 से 2 करोड़ तथा कुछ में इससे भी अधिक उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है, किंतु इन आँकड़ों की सटीकता से स्वतंत्र पुष्टि अभी शेष है। हालांकि यह पूरी जानकारी मीडिया से उठाई गई है। साथियों बात अगर हम चार महीने तक सुरक्षित रखा गया पार्थिव शरीर,शिया परंपरा और अभूतपूर्व राष्ट्रीय तैयारी को समझने की करें तो,इस पूरे आयोजन का सबसे असाधारण पक्ष यह है कि अयातुल्ला खामेनेई और उनके परिवार के 4 अन्य दिवंगत सदस्यों के पार्थिव शरीरों को लगभग चार महीने तक संरक्षित रखा गया। सामान्य इस्लामी परंपरा में मृत्यु के बाद शीघ्र दफन को सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन युद्ध, बड़े सुरक्षा संकट या अन्य असाधारण परिस्थितियों में विलंब की अनुमति दी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अवधि में शवों को रासायनिक संरक्षण (एम्बामिंग) के बजाय नियंत्रित तापमान वाले रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में रखा गया होगा, ताकि धार्मिक मान्यताओं का सम्मान बना रहे।युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण अंतिम संस्कार टालना केवल धार्मिक निर्णय नहीं था,बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति भी थी। ईरान को आशंका थी कि यदि युद्ध के दौरान इतने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए तो दुश्मन देश या आतंकी संगठन भीड़ या शीर्ष नेतृत्व को निशाना बना सकते हैं। इसी कारण अंतिम संस्कार तब तक स्थगित रखा गया जब तक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो गई। साथियों बात अगर हम तेहरान में शुरू हुए इस शोक समारोह के लिए राजधानी को अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सेना, पुलिस, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स,स्वयंसेवी संगठन और प्रशासनिक तंत्र को संयुक्त रूप से तैनात किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है और कुछ अवधियों के लिए हवाई क्षेत्र पर भी विशेष नियंत्रण रखा गया है। सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में पाँच करोड़ रोटियाँ, हजारों जल-छिड़काव केंद्र, सैकड़ों पार्किंग स्थल और करोड़ों श्रद्धालुओं जैसी तैयारियों के दावे सामने आए हैं। हालांकि इन सभी विशिष्ट आँकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन्हें ईरानी या अन्य मीडिया के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि स्थापित तथ्य के रूप में। दूसरी ओर, यह स्पष्ट है कि आयोजन के पैमाने को देखते हुए भोजन,पेयजल, चिकित्सा सहायता,भीड़ नियंत्रण और परिवहन की सटीकता से व्यापक व्यवस्थाएँ की गई है। साथियों, इस अंतिम यात्रा को केवल एक राज्य समारोह नहीं बल्कि शिया धार्मिक संस्कृति की निरंतरता के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। शिया परंपरा में शहादत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और करबला की ऐतिहासिक स्मृति आज भी धार्मिक और राजनीतिक चेतना का आधार मानी जाती है। इसी कारण ईरानी नेतृत्व खामेनेई की मृत्यु को राष्ट्रीय प्रतिरोध और धार्मिक धैर्य के प्रतीक के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।दूसरी ओर, यह भी सत्य है कि ईरान के भीतर सभी नागरिक इस आयोजन को एक समान दृष्टि से नहीं देखते। निर्वासित विपक्षी समूह और कुछ आलोचक इसे राज्य- प्रायोजित राजनीतिक प्रदर्शन बताते हैं, जबकि समर्थकों के लिए यह राष्ट्रीय सम्मान और श्रद्धांजलि का अवसर है। इसलिए यह अंतिम संस्कार केवल शोक का नहीं, बल्कि ईरान के भीतर मौजूद राजनीतिक मतभेदों का भी दर्पण बन गया है। साथियों बात अगर हम मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया- एकजुटता और व्यावहारिक राजनीति का मिश्रण को समझने की करें तो रिपोर्टों के अनुसार लगभग 30 देशों के प्रतिनिधिमंडलों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। रूस, पाकिस्तान तथा क्षेत्र के कई देशों के प्रतिनिधियों के आने की खबरें हैं, जबकि अधिकांश पश्चिमी देशों की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि कईमुस्लिम और क्षेत्रीय देश ईरान के साथ संवाद बनाए रखना चाहते हैं, भले ही उनकी अपनी विदेश नीतियाँ अलग-अलग हों।क्या यह सचमुच विश्व इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार हो सकता है?इतिहास में अनेक विशाल अंतिम संस्कार हुए हैं, जिनमें 1989 में अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी का अंतिम संस्कार भी शामिल है, जिसमें लगभग एक करोड़ लोगों की उपस्थिति का व्यापक उल्लेख मिलता है। वर्तमान आयोजन के बारे में कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इसकी भीड़ उस रिकॉर्ड को भी पार कर सकती है। हालांकि अंतिम और स्वतंत्र रूप से सत्यापित आँकड़े उपलब्ध होने के बाद ही यह निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि यह वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार था या नहीं।यह अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मध्य-पूर्व की बदलती शक्ति-संरचना का भी प्रतीक माना जा रहा है। ईरान अपने समर्थक समूहों और सहयोगी देशों को यह संदेश देना चाहता है कि नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद उसकी राजनीतिक और सैन्य संरचना कायम है। दूसरी ओर अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह आयोजन भविष्य की वार्ताओं, क्षेत्रीय गठबंधनों और सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। साथियों, इस समारोह में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के आने की भी खबरें हैं। चीन ने वरिष्ठ प्रतिनिधि भेजने की घोषणा की है, जबकि क्षेत्रीय सहयोगी देशों और कई धार्मिक प्रतिनिधि मंडलों की भागीदारी की भी सूचना है। भारत से भी कुछ सार्वजनिक हस्तियों के शामिल होने की मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि आधिकारिक भारतीय सरकारी प्रतिनिधित्व की प्रकृति अलग-अलग रिपोर्टों में भिन्न बताई गई है। इस प्रकार यह आयोजन केवल एक अंतिम संस्कार नहीं रह गया है यह ईरान की आंतरिक राजनीति, शिया धार्मिक पहचान, राष्ट्रीय सुरक्षा, जन-समर्थन और वैश्विक कूटनीति का संगम बन गया है।

आने वाले वर्षों में इतिहासकार संभवतः इसे केवल एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक -प्रतीकात्मक आयोजनों में से एक के रूप में भी सटीकता से देखेंगे। साथियों बात कर हम अमेरिका पर प्रभाव- कूटनीतिक दबाव और नई रणनीतिक चुनौती को समझने की करें तो यदि अंतिम संस्कार में विशाल जनसमूह और अनेक देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होते हैं,तो यह अमेरिका के लिए केवल एक शोक समारोह नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार घाती, मो० : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। [illegible]

युवा विकसित देवरिया के निर्माण में निभाएं सक्रिय भूमिका - सांसद शशांक मणि

भटनी देवरिया।

नगर पंचायत क्षेत्र के रामपुर खोरीबारी में सोमवार को आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में सदर सांसद शशांक मणि ने युवाओं से विकसित देवरिया के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब युवा शिक्षा, तकनीक, कौशल विकास और नवाचार को अपनाकर आगे बढ़ेंगे। सांसद ने कहा कि क्षेत्र में तकनीकी

रामपुर खोरीबारी में युवा संवाद कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीक व कौशल विकास पर दिया जोर

एवं स्पेस शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकें। उन्होंने विद्यार्थियों से बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने तथा डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने शिक्षा, रोजगार और क्षेत्र के विकास से जुड़े प्रश्न रखे, जिनका सांसद ने विस्तार से उत्तर दिया। इस अवसर पर विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, भाजपा जिला मंत्री डॉ. हेमंत मिश्रा, मीडिया प्रभारी प्रभाकर तिवारी, सचिंद्र शाही दीपू, मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा, हितेन्द्र तिवारी, सुधीर श्रीवास्तव, शेषनाथ कुशवाहा, ब्रह्मानंद मिश्रा, मुन्ना राय, सुधांशु राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भाजपा का बूथ स्तर पर पुष्पांजलि व पौधरोपण कार्यक्रम

पडरौना, कुशीनगर।

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले भर में बूथ स्तर पर पुष्पांजलि एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने बूथों पर डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प लिया। इसी क्रम में जिला महामंत्री विवेकानंद शुक्ल के नेतृत्व में जिला मंत्री विश्वरंजन कुमार आनंद, नगर मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर त्रिपाठी एवं अन्य पदाधिकारियों ने पडरौना नगर में जिला उपाध्यक्ष मीनू जिंदल के आवास पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद रविंद्र नगर स्थित भाजपा कार्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री विवेकानंद शुक्ल ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रनिर्माण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत की अखंडता के प्रतीक थे। उन्होंने एक शिक्षाविद्, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी राजनेता एवं प्रखर राष्ट्रभक्त के रूप में देश को नई दिशा दी। जिला मंत्री विश्वरंजन कुमार आनंद ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने तथा राष्ट्रीय एकता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर उनके सपने को साकार किया गया और राष्ट्र प्रथम की भावना को सशक्त रूप मिला। कार्यक्रम में पडरौना देहात मंडल अध्यक्ष रामजीत चौहान, भीखम प्रसाद, विष्णु जायसवाल, मनीष विश्वकर्मा, विकास जायसवाल, मनीष चौधरी, अभय यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दोनों युवक गंभीर घायल

कसया, कुशीनगर। कसया नगर के पडरौना मार्ग पर सोमवार को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर धूस रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, रविंद्र नगर धूस निवासी भानु प्रताप गौड़ कसया से अपने घर जा रहे थे। बैरिया चौराहे से कुछ आगे पहुंचते ही उनकी बाइक की सामने से आ रहे बेलवा कारखाना निवासी प्रतीक की बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को सड़क किनारे सुरक्षित कर एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कसया भेजा।

मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को सुरक्षा व हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी

भटनी पुलिस ने नर्सिंग संस्थान में जागरूकता अभियान चलाकर वितरित किए पम्पलेट

भटनी देवरिया।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देशन में सोमवार को मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं शक्ति दीदी अभियान के तहत भटनी पुलिस ने रामरेखा राय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, मुहराव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम के दौरान उपनिरीक्षक देवेन्द्र यादव, कांस्टेबल अरविन्द यादव एवं रिक्रूट महिला कांस्टेबल बेबी यादव ने छात्राओं को पम्पलेट वितरित कर महिला सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने डायल-112, महिला हेल्पलाइन-181, वूमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, साइबर हेल्पलाइन-1930, एंबुलेंस सेवा-108 सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के बारे में जागरूक करते हुए किसी भी समस्या की स्थिति में इन सेवाओं का तत्काल उपयोग करने की अपील की।

नेबुआ रायगंज में गंदगी से बजबजा रहीं नालियां, जलभराव से ग्रामीण परेशान

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम पंचायत नेबुआ रायगंज के नेबुआ टोला और केरवनिया टोला में गंदगी एवं जल निकासी

की समस्या को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार नेबुआ टोला में करीब 50 मीटर लंबी नाली का निर्माण वर्षों से अधूरा पड़ा है। उनका कहना है कि पुरानी नाली का निर्माण पूर्व प्रधान ब्यास वर्मा के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन वर्तमान में उसकी नियमित सफाई नहीं कराई जा रही है। नालियों में कचरा और गाद जमा होने से जल निकासी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि गांव की समस्याओं के समाधान का वादा करते हैं, लेकिन बाद में विकास कार्यों और साफ-सफाई की व्यवस्था की अनदेखी की जाती है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन से नालियों की तत्काल सफाई कराने और अधूरी नाली का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के साथ आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे।

एक साल से आदेश अटकाने वाले राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार पर बड़ी कार्रवाई

देवरिया।

जनता की समस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली और अदालती आदेशों को दबाकर बैठने वाले राजस्व कर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को सदर तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने लचर कार्यप्रणाली पर बड़ी कार्रवाई की। पंजिकाओं के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा धारा-116 का आदेश एक वर्ष पूर्व पारित होने के बावजूद अब तक उसका अनुपालन नहीं कराया गया। इस गंभीर लापरवाही पर जिलाधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर दी। वहीं, विशुनपुरा बाजार के तत्कालीन लेखपाल और वर्तमान राजस्व निरीक्षक उपेंद्र प्रजापति को भी दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। समाधान दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिजीत आर शंकर ने संयुक्त रूप से फरियादियों की समस्याओं को सुना। मंच से अधिकारियों को दोटूक हिदायत दी गई कि धारा-24, धारा-116 और निर्विवाद वरासत के प्रकरणों में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं होगी। जनसुनवाई में ग्राम बसडीला की सीमा शर्मा और पथरदेवा की प्रेमलता ने अपनी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें रखीं, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित थाना प्रभारियों और तहसीलदारों को मौके पर जाकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सिरजम के रामानंद यादव ने पैमाइश आदेश के बाद भी काम रोके जाने की समस्या उठाई, जिस पर उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया। सदर तहसील में इस दौरान कुल 144 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 8 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष बचे 136 मामलों को एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण की समय-सीमा तय कर संबंधित विभागों को भेजा गया है। सबसे अधिक 44 मामले पुलिस और 42 मामले राजस्व विभाग से जुड़े रहे। जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदारों को फील्ड में लेखपालों और कानूनगो के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

सदर समाधान दिवस में राजस्व कर्मियों पर गिरी गाज- एक को प्रतिकूल प्रविष्टि, दूसरे को नोटिस

*बिजली कटौती पर बरहज में सड़कों पर उतरी जनता, एसडीएम को सौंपा मांगपत्र

*रात में मुख्यालय से नदारद रहने वाले बिजली अभियंताओं पर कार्रवाई सहित पांच सूत्रीय मांगों पर सात दिन का अल्टीमेटम

बरहज (देवरिया)। क्षेत्र में जारी अघोषित बिजली कटौती, खस्ताहाल सड़कों और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ सोमवार को नागरिकों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। पूर्व टाउन चेयरमैन अजीत जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने नगर में विशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ के कारण नगर के प्रमुख मार्गों पर कुछ समय के लिए यातायात की गति धीमी रही। जुलूस विभिन्न चौराहों से गुजरता हुआ तहसील परिसर पहुंचा, जहां नागरिक अपनी मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। तहसील परिसर में करीब बीस मिनट तक चले गतिरोध के बाद मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी को प्रदर्शनकारियों ने पांच सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए अजीत जायसवाल ने सीधे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन), एसडीओ और जेई जैसे जिम्मेदार अधिकारी नियमों के विरुद्ध जिला या क्षेत्र मुख्यालय पर रात्रि विश्राम नहीं करते हैं, जिससे देर रात फॉल्ट होने पर जनता को घंटों त्रस्त रहना पड़ता है। सौंपे गए मांगपत्र में अघोषित विद्युत कटौती पर तत्काल रोक लगाने, बंद पड़े गौरा मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कराने, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने और सभी जनसमस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने की मांग शामिल है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर इन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे अटल तिराहे पर क्रमिक एवं आमरण अनशन शुरू करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। इस दौरान प्रो. अजय कुमार मिश्र, प्रदीप जायसवाल, विजय रावत सहित भारी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।

नितिन नवीन पर विपक्ष के कटाक्ष पर पीएम का जवाब; प्रधानमंत्री बीजेपी चीफ की सादगी पर क्या बोले?

नई दिल्ली। विपक्षी दलों ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर तीखे कटाक्ष किए। उसके बाद हुई जुबानी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा अध्यक्ष की सादगी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने नवीन के आचरण और उच्च नैतिक चरित्र की सराहना की। उन्होंने नवीन के कॉलेज मित्र एक जाने-माने पत्रकार की पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में नवीन के विनम्र शुरुआती जीवन और जमीन से जुड़े रहने की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। पत्रकार के जिस अंश को पीएम मोदी ने साझा किया है, इसमें नवीन के छात्र जीवन की सादगी का उल्लेख है। इसमें लिखा गया है कि 1998 में दिल्ली में पढ़ाई के दौरान नवीन एक विधायक के बेटे होते हुए भी साधारण जीवन जीते थे। वह दोस्तों के साथ सस्ते भोजन साझा करते थे। नवीन दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों से यात्रा करते थे। खर्च कम करने के लिए वह घर के कामों में भी समान रूप से भाग लेते थे।

पत्रकार के अनुसार, नवीन कभी अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रदर्शन नहीं करते थे। उन्होंने कभी कोई विशेष सुविधा नहीं मांगी। वे एक कमरा साझा करते थे और पैसे बचाने के लिए 20 रुपये के भोजन को भी बांट लेते थे। नवीन महंगी परिवहन के बजाय डीटीसी बसों पर निर्भर रहते थे। उन्होंने छात्र जीवन भर एक साधारण जीवन शैली अपनाई। एक अन्य पोस्ट में पत्रकार ने दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन क्षेत्र में उनके जीवन का वर्णन किया। नवीन और कुछ दोस्त पटपड़गंज में एक साधारण आवास में रहते थे। वे एक उचित फ्लैट का खर्च नहीं उठा सकते थे। नवीन किराया, भोजन और कॉलेज के खर्चों के लिए 2,000 रुपये का मासिक बजट रखते थे। समूह नाश्ता बनाने, बर्तन धोने और कमरा साफ करने जैसी घरेलू जिम्मेदारियां साझा करता था। पत्रकार ने नवीन को अनुशासित, मिलनसार और विनम्र बताया।

प्रधानमंत्री की यह प्रशंसा भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आई है। यह विवाद दान चोरी के आरोपों को लेकर तेज हुआ है। नवीन ने लखनऊ में एक भाजपा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से हिंदू धर्म को इतना कमजोर न समझने को कहा। नवीन की टिप्पणी पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए पूछा, आप कौन हैं? दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी केजरीवाल पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की टिप्पणियां हताशा और निराशा को दर्शाती हैं। गुप्ता ने एक्स पर नवीन का परिचय देते हुए उनकी राजनीतिक यात्रा और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नवीन 46 वर्ष के हैं और भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का चार बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दिल्ली मंत्री परवेश वर्मा ने भी केजरीवाल पर तंज कसा। वर्मा ने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को हराया था।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी-चंपत राय का इस्तीफा मंजूर , कृष्ण मोहन बनाये गये महासचिव

अयोध्या।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। कृष्ण मोहन दलित समाज से हैं। चढ़ावा चोरी के बाद हुई पहली बैठक 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बोले- चंपत राय ने कहा है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो हुआ वह कष्टदायी है। इससे हम सब दुखी हैं। चढ़ावा चोरी लज्जास्पद घटना है। बैठक में ट्रस्टी के. पाराशरन ने कहा था कि त्यागपत्र देते हैं इसे स्वीकार करना ट्रस्ट के संविधान में है। इसलिए इस्तीफा स्वीकार किया गया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की फिर बैठक होगी। कृष्ण मोहन ने कहा- चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा दिलाएंगे। प्रबंधन की कमियों का फायदा उठाया गया, कमियों को दूर करेंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। समाज में अविश्वास है। विश्वास को दोबारा स्थापित करेंगे।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सोमवार को हुई बैठक का वीडियो सामने आया है। इसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, डीएम अयोध्या समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए, जबकि पदेन सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

ट्रस्ट ने 4 सोने-चांदी की वस्तुएं दिखाईं, इनकी चोरी का दावा था

ट्रस्ट की 5 बड़ी बातें द

1. ट्रस्ट को दान के जरिए 3,264 करोड़ रुपए मिले थे। इनमें से 2,370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं।

2. ट्रस्ट की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं से 582 करोड़ रुपए की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई। इसमें से 391 करोड़ रुपए ट्रस्ट के संचालन और अन्य खर्चों पर खर्च किए गए। बाकी राशि बैंक खातों में सुरक्षित है।

3. एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। गोपाल नागरकट्टे का नाम विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से हटाने का फैसला।

4. नकद दान के अलावा श्रद्धालुओं ने भेंट अर्पित की। अब तक ऐसी 2,926 भेंट प्राप्त हुई हैं। इन सभी का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है। हर साल एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म सभी भेंटों का भौतिक सत्यापन करती है।

5. कोई श्रद्धालु अपनी दी हुई भेंट की जानकारी लेना चाहता है तो वह ट्रस्ट के किसी अधिकारी से अयोध्या आकर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

बिना जेब का कुर्ता पहनेंगे पुजारी, चढ़ावे की होगी कड़ी निगरानी

अयोध्या विवाद के बाद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला

देहरादून। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान राशि को लेकर उपजे विवाद और उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर से आई चोरी की खबरों के बाद अब धर्मनगरी हरिद्वार के प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। मंदिर प्रशासन ने दान और चढ़ावे की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए नई नियमावली लागू की है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत डॉ. रविंद्र पुरी महाराज ने स्पष्ट किया है कि अब मंदिर में सेवा देने वाले पुजारी बिना जेब वाला कुर्ता पहनेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोई भी पुजारी चढ़ावे की राशि को अपनी जेब में न रख सके। यदि कोई भी पुजारी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए दान का पैसा अपने पास रखता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निगरानी के लिए समिति का गठन

दान व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इस समिति में मंदिर प्रशासन के सात पुजारियों को भी शामिल किया गया है, जो चढ़ावे की पूरी निगरानी करेंगे। इसके साथ ही, मंदिर के सभी कर्मचारियों और श्रद्धालुओं पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है।

प्रसाद और चढ़ावे पर पाबंदी

ट्रस्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि मंदिर में एक बार चढ़ाए गए नारियल, प्रसाद और फूलों को दोबारा नहीं चढ़ाया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि पुराने चढ़ावे को दोबारा श्रद्धालुओं को बेच दिया जाता है, जिस पर अब पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की जा रही है।

सीएम रेखा गुप्ता ने जरूरतमंद परिवारों को अहम आर्थिक सहायता दी, कहा- हर संकट में आपके साथ खड़ी है सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रोहतास नगर और बवाना के कई जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे किसी भी नागरिक को सरकार बिना सहायता के नहीं छोड़ेगी। यह सहायता सोमवार, 6 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वितरित की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल कल्याणकारी योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि जरूरत के समय सहायता सीधे लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर परिवार की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुना जाएगा और प्रशासन समय पर राहत उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। इस कार्यक्रम में रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन भी उपस्थित रहे। रोहतास नगर और बवाना के कई परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सा, सामाजिक या आर्थिक संकट का सामना कर रहे कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तत्काल राहत मिलने से परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक और मानसिक दबाव कम होता है।

दिल्ली सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री जन सेवा सदन को नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का मंच बनाया गया है। यहां नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। वे लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करते हैं। पिछले कुछ महीनों में इसी मंच के माध्यम से कई जरूरतमंद परिवारों को राहत और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सहायता वितरण में होने वाली देरी को कम करना, मामलों की बेहतर निगरानी करना और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाना है। दिल्ली सरकार का कहना है कि जन सेवा सदन केवल शिकायत निवारण का केंद्र नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को सरकारी सेवाओं और सहायता योजनाओं तक आसानी से पहुंचाने का माध्यम भी है। इस व्यवस्था के तहत अधिकारियों को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जनसुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की जिम्मेदारी दी गई है।

राहुल का केंद्र पर बड़ा आरोप- मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल केवल नारे बनकर रह गए हैं

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की दो प्रमुख पहल मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल केवल नारे बनकर रह गई हैं तथा उसकी एमएसएमई विरोधी नीतियां इन उद्योगों का गला घोंट रही हैं। कांग्रेस नेता ने जयपुर में स्थानीय बस और ट्रक बॉडी बिल्डर्स की फैक्ट्री का दौरा करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में मेहनत और हुनर से भारत का भविष्य गढ़ने वाले कारीगर देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाए गए कुछ नियम देशभर के छोटे बस और ट्रक बॉडी निर्माण उद्योगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। गांधी ने आरोप लगाया कि बसों में तकनीकी खराबी के कारण लगने वाली आग का दोष उन बॉडी बिल्डर्स पर मढ़ा जा रहा है, जबकि उनका काम केवल वाहनों की बॉडी तैयार करना है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन एमएसएमई को

प्रोत्साहन और सहाय मिलना चाहिए, उनकी गतिविधियों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां छोटे उद्योगों के हितों के अनुरूप नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि ऐसी फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो केवल कारोबार ही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि पारंपरिक हुनर बिखरेगा, रोजगार के अवसर कम होंगे और इसका असर आम लोगों पर बढ़ती महंगाई के रूप में भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे अधिक कीमत मेहनतकश और हुनरमंद भारतीयों को चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने राजस्थान के स्थानीय बस और ट्रक बॉडी बिल्डर्स से मुलाकात की, जहां उन्हें ऐसा भारत देखने को मिला जो अपने हाथों से रोजगार भी बनाता है और देश की रफ्तार भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि इन कारीगरों की विश्वस्तरीय कारीगरी को सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें नियमों के बोझ तले काम बंद करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की एमएसएमई विरोधी नीतियां इन उद्योगों का गला घोंट रही हैं। उन्होंने कहा, जब छोटे उद्योग हारते हैं, तब सिर्फ फैक्ट्री नहीं बंद होती, बल्कि भारत का हुनर हारता है और मेहनतकश कारीगर बेरोजगार होता है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी कारीगरों के अधिकार उनसे छिनने नहीं देगी।

650 करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप का लोकनायक अस्पताल पर हल्लाबोल

नई दिल्ली। दिल्ली में 650 करोड़ रुपये के कथित दवा खरीद घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर मानव श्रृंखला बनाई। आप ने आरोप लगाया कि डा वत्सला अग्रवाल को उनके खिलाफ विजिलेंस जांच लंबित होने और वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी कर डीजीएचएस नियुक्त किया गया। आप ने दावा किया कि सरकार ने अस्पतालों की स्थानीय खरीद की व्यवस्था समाप्त कर खरीद की प्रक्रिया केंद्रीय स्तर पर सीपीए के माध्यम से कर दी, जिससे पूरे सिस्टम का नियंत्रण एक ही अधिकारी के हाथ में आ गया। आरोप लगाया कि दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर की गई। कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि महंगे दामों पर ओआरएस, चादर और अन्य सामान खरीदे गए,

जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में दवाओं और जांच सेवाओं पर असर पड़ा। मॉडल टाउन के पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने भी नियुक्तियों और खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, कथित मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी तथा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मामले के कथित मास्टरमाइंड राजीव रंगीला को गिरफ्तार करने के बजाय देश छोड़कर जर्मनी जाने दिया गया।

रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई ट्रेन सेवाओं को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नांदेड़-मुंबई और टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखायी। इसके साथ ही उन्होंने टनकपुर-पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक किए जाने का भी उद्घाटन किया। वैष्णव ओडिशा के दौरे पर हैं, जहां वह भगवान जगन्नाथ की आगामी रथ यात्रा के मद्देनजर रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ-साथ दिन में बाद में ओडिशा से शुरू होने वाली दो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने नई रेल सेवाओं की शुरुआत यहां रेल भवन से की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि नई रेल सेवाओं से रेल संपर्क बेहतर होगा और यात्रियों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में रहने वाले सिख समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, तराई क्षेत्र में रहने वाले हमारे सिख भाई-बहनों की ओर से लंबे समय से इस रेल सेवा की मांग की जा रही थी। आज नांदेड़ से वाशिम और हिंगोली होते हुए मुंबई के लिए भी रेल सेवा शुरू की गई है, जिससे विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों का मुंबई

से संपर्क बेहतर होगा। पीलीभीत, आगरा और टनकपुर को जोड़ने वाली कुछ अन्य रेल सेवाएं भी शुरू की गई हैं। वैष्णव ने कहा कि रेलवे खटीमा और बनबसा स्टेशनों पर इस ट्रेन के ठहराव की मांग पर भी विचार करेगा। उन्होंने कहा, यदि यह संभव हुआ, तो इस ट्रेन का ठहराव खटीमा और बनबसा में भी निश्चित रूप से दिया जाएगा। रेल मंत्री ने यह भी घोषणा की कि टनकपुर-पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले विशेष ट्रेन के रूप में संचालित होने वाली टनकपुर-आगरा रेल सेवा को अब नियमित कर दिया गया है। रेलवे की पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वैष्णव ने कहा कि इस अवधि में लगभग 37,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं और रेलवे नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केरल में ओणम पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 100 विशेष ट्रेन चलाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुरी में रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ओडिशा से राज्यसभा सदस्य वैष्णव ने कहा कि राज्य में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की रेल परियोजनाओं पर काम जारी है।

इस्तीफा नहीं, कड़ी सजा मिले- राम मंदिर ट्रस्ट के फैसले पर विपक्ष का हमला

नई दिल्ली। अयोध्या के राम मंदिर चंदा विवाद में सोमवार को जहां ट्रस्ट की ओर से बैठक की गई। वहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने मीडिया के सामने आकर बताया कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ ही अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर किया गया है। ट्रस्ट की ओर से इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर बचाने की कोशिश हो रही है।

इतना बड़ा रैकेट वर्षों तक फलता-फूलता रहा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर करके राम मंदिर ट्रस्ट ने पूरी तरह यह स्वीकार कर लिया है कि पिछले एक महीने से देश को हिला देने वाली चंदा चोरी की रिपोर्ट वाकई सत्य है। यह स्वागत योग्य खबर है कि प्रभु राम के पावन मंदिर से वे लोग हटाए जा रहे हैं जो वर्षों तक इसे लूटते रहे। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हास्यास्पद बात यह है कि यह घोषणा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष द्वारा की गई- वही व्यक्ति जिस पर इसके वित्त की निगरानी, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इसकी संपत्तियों की रक्षा करने का दायित्व होता है। वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता, और न ही ट्रस्ट का कोई अन्य सदस्य इस दायित्व से किनारा कर सकता है, जिनकी देखरेख में इतना बड़ा रैकेट वर्षों तक फलता-फूलता रहा।

कृष्णमोहन को महासचिव बनाए जाने पर भी सवाल

उन्होंने आगे लिखा, मूर्खता यहीं समाप्त नहीं होती। आरएसएस के पूर्व उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्णमोहन

को राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव नियुक्त कर दिया गया है, जबकि खुद उन पर इस घोटाले को दबाने में भूमिका के आरोप हैं। उन्हें बड़े दायित्व से पुरस्कृत करने के बजाय ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए था। देश टुकड़े-टुकड़े में इस्तीफे नहीं चाहता।

उस ट्रस्ट को पूरी तरह भंग करके उसका पुनर्गठन चाहिए। देश ट्रस्ट के हर सदस्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट-निगरानी में एक स्वतंत्र जांच चाहता है। जवाबदेही सिर्फ ट्रस्ट पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री तक भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जिन्होंने ट्रस्ट का गठन किया और उसके कई सदस्यों की नियुक्ति की। योगी आदित्यनाथ सरकार तक, जिसने वर्षों तक इस लूट और डकैती को प्रभावी जांच के बिना चलते रहने दिया और उस आरएसएस-बीजेपी माफिया की भी जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है, जिसने दशकों से करोड़ों भारतीयों की कीमत पर खुद को मालामाल करने के लिए भगवान राम के नाम का दोहन किया है।

केजरीवाल बोले- इस्तीफा नहीं सजा मिले

ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिंदु सनातनी को इस्तीफा नहीं, कड़ी सजा चाहिए। इस्तीफा लेकर उन्हें बचाने की कोशिश मत करो।

शिवसेना ने भी साधा निशाना

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि खबरों के मुताबिक, अयोध्या में राम मंदिर के दो ट्रस्टियों के इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई है। ऐसा लगता है कि यह फैसला दान और राशि में धोखाधड़ी के आरोपों की वजह से लिया गया है। लेकिन इस बात का क्या कि उन्हें भाजपा की केंद्र सरकार ने ही नियुक्त किया था? मंदिर में हुई चोरी के बारे में क्या, उस मंदिर को लूटने की हिम्मत और अपराध के बारे में क्या, जिस पर भाजपा का पिछले दो दशकों का पूरा अभियान टिका था? उन्होंने आगे कहा कि हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जरूरत है, जिसकी निगरानी या तो सुप्रीम कोर्ट करे या फिर वह किसी पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में हो। भाजपा हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती।

सपा क्या बोली?

सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि महंत नृत्य गोपाल दास ने लगभग 20 दिनों के बाद, जब मंदिर में कथित चोरी का मामला सामने आया और पूरा देश इसके बारे में जान गया, तब जाकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें तत्काल इस मामले पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी और यह मांग करनी चाहिए थी कि राम मंदिर ट्रस्ट में हुई कथित चोरी की जांच किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए, ताकि असली दोषी जनता के सामने आ सकें।

भारत की पासपोर्ट रैंकिंग को लेकर खड़गे ने पीएम मोदी की आलोचना, कहा- तथ्य उनके दावों को गलत साबित करते हैं

नई दिल्ली।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भारत की गिरती पासपोर्ट रैंकिंग और सालाना पर्यटकों की संख्या में कमी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को ÷भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस प्रमुख ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल सिटिजन सॉल्यूशंस का हवाला दिया, जिनके अनुसार भारत वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स में क्रमश: 80वें और 125वें स्थान पर खिसक गया है। उन्होंने पासपोर्ट फीस में हालिया बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सेवाओं में सुधार करने के बजाय, केंद्र ने पासपोर्ट को और महंगा कर दिया है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, मोदी सरकार की नीतियां भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। पीएम मोदी ने 2018 में दावा किया था कि विदेशों में यात्रा करने और रहने वाले लोग आज भारतीय पासपोर्ट के सम्मान और ताकत को जानते हैं। वह ताकत कहां दिखती है? तथ्य उनके दावों को गलत साबित करते हैं÷ उन्होंने आगे कहा, एक वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में, भारत 2013 में 74वें स्थान से गिरकर जून 2026 में 80वें स्थान पर आ गया है। [वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम] एक अन्य वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स भारत को 2026 में 125वें खराब स्थान पर रखता है। [ग्लोबल सिटिजन सॉल्यूशंस] सेवाओं में सुधार करने के बजाय, मोदी सरकार ने पासपोर्ट को और महंगा कर दिया है। पासपोर्ट फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये कर दी गई है, जबकि तत्काल शुल्क 5,000 रुपये तक बढ़ गया है।

नाकामी छिपाने के लिए एनआरआई डेटा मिलाने का आरोप लगाया

खड़गे ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या वह एनआरआई के आगमन को विदेशी पर्यटकों के डेटा के साथ मिलाकर अपनी विफलता को छिपा रही है और आरोप लगाया कि भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन अभी भी कोरोना-पूर्व के समय से कम है। ÷भारत आने-जाने में आसानी के बावजूद, विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी कोविड से पहले के स्तर से कम है। यह 2019 में 10.93 मिलियन से घटकर 2024 में 9.95 मिलियन हो गई है। क्या मोदी सरकार एनआरआई के आने की संख्या को विदेशी पर्यटकों के डेटा के साथ मिलाकर इस नाकामी को छिपा रही है? भारत का आधिकारिक वीजा आवेदन पोर्टल अभी भी इतना पुराना और उलझाने वाला क्यों है कि यह 1990 के दशक की किसी वेबसाइट जैसा लगता है? अतिथि देवो भव की धरती भारत में कोई भी पर्यटकों का इस तरह स्वागत नहीं करना चाहेगा, कांग्रेस प्रमुख ने कहा।

टूरिज्म में नहीं हुआ कोई सुधार

उन्होंने आगे कहा, अगर पासपोर्ट कमजोर है, टूरिज्म में सुधार नहीं हुआ है, वीजा सेवाएँ खराब हैं और नागरिक घटिया सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो आखिर वह बहुत ज्यादा प्रचारित वैश्विक सम्मान कहाँ है? सच्चाई कड़वी होती है। भारत की साख को नुकसान पहुँचा है। श्रेय- मोदी सरकार।